नवभारत
1934 से
www.onevaibharat.com नागपुर, शुक्रवार 9 फरवरी, 2018 ■ पृष्ठ : 22 मूल्य : ₹ 5.00 ■ फाल्गुन कृष्ण 9

पोर्टल बताएगा जमीन की सेहत

समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता है NBSS & LUP

नवभारत PERSON OF THE WEEK

व्यापार प्रतिनिधि

नागपुर. भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज भी वैज्ञानिक आधार पर खेती की ओर कम ही रुझान देखने मिलता है. किसान वर्षों से चल रहे पैटर्न या दूसरों की देखा देखी फसलों का चयन करते हैं. वहीं यदि जमीन के उपजाउपन और उपलब्ध पानी के अनुसार खेती की जाए तो ज्यादा लाभ प्राप्त किया **जा सकता है.** राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमि उपयोग संस्थान पिछले कई वर्षों से इस दिशा में **कार्यरत है.** संस्थान की ओर से केंद्र और राज्य **सरकार को** जमीन की उर्वरा शक्ति से संबंधित **इनपुट्स** देता रहा है. अब संस्थान एक **कदम आगे** जाकर जियो पोर्टल बनाने पर काम **कर रहा है.** किसान केवल खसरा नंबर डालकर **अपनी** जमीन की सेहत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. जमीन की उर्वरा शक्ति कैसी है. कहां पानी है, पानी को कैसे लिंक करे इसकी जानकारी किसान अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे. संस्थान के निदेशक डा. एस.के. सिंह बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से किसानों की काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा.

डा. एस.के. सिंह, निदेशक, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमि उपयोग संस्थान

घट रहा पोषक तत्वों का प्रमाण

ज्यादा गहराई में खेती, नियंत्रित खाद प्रबंधन के अभाव और पानी के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में जमीन की **उर्वरता में** कमी आई है. उन्होंने बताया कि **जमीन में** पोषक तत्वों का प्रमाण कम होने की **बात सामने** आई है. महाराष्ट्र के मालेगांव, **नगर, धुले,** जलगांव, सांगली जिलों का इसमें **समावेश है** और जल्द ही उपाय योजना की **जानी चाहिए.** इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, **दिल्ली, उत्तरप्रदेश,** बिहार, पश्चिम बंगाल के समुद्री किनारे के भाग, कर्नाटक, तेलंगाना सहित आंध्रप्रदेश और गुजरात के कुछ भाग भी इसी समस्या से प्रभावित है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में 35 से 80 टन प्रति हेक्टेयर पोषक तत्व उपलब्ध है.

विदर्भ की हालत अच्छी

उपजाउपन के मामले में विदर्भ की जमीनों की हालत कुछ ठीक है. यहां जमीन में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर पोषक तत्व उपलब्ध है. हालांकि इसमें अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, मराठवाड़ा के लातूर जै कुछ ही जिलों का समावेश है. अमरावती में सतपुड़ा पर्व शृंखला के कारण इस भाग में आद्रता बनी रहती है जिससे संत्र की फसल को फायदा होता है.

1958
में हुई थी स्थापना

84
वैज्ञानिक कार्यरत

कृषि मंत्रालय के तहत कार्यरत

अखिल भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण, जि अब भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण के नाम जाना जाता है. इसकी स्थापना 1958 में की गई थ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत यह संस्था देश में मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि संसाधन के प्रतिचित्रण के क्षेत्र एक प्रतिष्ठित संस्थान है. संस्था द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों भूमि उपयोग मानचित्र प्रकाशित किये जाते हैं. भूमि उपयोग अ इसमें परिवर्तन का किसी क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिक पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है.

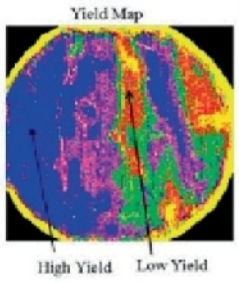

है पूरे देश की मिट्टी का नक्शा

उन्होंने बताया कि किसान और रिसर्च के बीच के गैप को कम करने का प्रयास संस्थान कर रहा है. अलग-अलग क्षेत्र की जमीनों के लिए हमने एडवायजरी विकसित की है. किस जमीन में कौनसी फसल ली जा सकती है, इसकी भी सलाह हम देते हैं. हालांकि हमारा मुख्य मकसद जमीन की हेल्थ का डाटा बनाकर केंद्र व राज्य सरकार को मुहैया कराना होता है. उनके जरिए यह एडवायजरी किसानों तक पहुंचाई जाती है. जमीन का इस तरह का अध्ययन करने वाला देश का यह एकमात्र संस्थान है. हमारे पास देश की पूरी मिट्टी का नक्शा है. इतना बड़ा डेटा बेस शायद ही किसी के पास होगा. क्राप जोन्स भी हमने निर्धारित कर रखे हैं. 84 वैज्ञानिकों की टीम हमेशा किसानों के हित में सायल सर्वे में लगी रहती है. वेस्ट लैंड में क्या स्कोप है इस बारे में भी हम जानकारी मुहैया कराते हैं. विभिन्न सरकारी महकमे के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का भी काम किया जाता है. कही जमीन के उपजाउपन में कमी आ रही हो तो इसे सुध करने की भी जानकारी संस्थान मुहैया कराता है.